

नहीं देश में हम तुम्हें, दे पायेंगे काम।
जाकर बनें विदेश में, उनके आप गुलाम।
उनके आप गुलाम, उन्हीं से नाता जोड़ें।
जितनी जल्दी बने, हमारा पीछा छोड़ें।
कह साहिल कविराय, उदारों अमी टोकरी।
परेशान मत करें, मांगकर हमें नौकरी।



प्रस्तुति : डॉ. राजेन्द्र साहिल

FOLLOW US ON @UTURNTIMENEWS

VOL. 03 | ISSUE 166 | THURSDAY DATE 09-07-2026 | RS 3 | PAGE-8 | PUBLISHED BY: DELHI | HINDI DAILY NEWSPAPER Visit at : www.uturntime.com

सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध : डॉ. पंकज

» दिल्ली, यूटर्न/ 08 जुलाई ।

दिल्ली के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

डॉ. सिंह ने आज यहां सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए आईटी ट्रेनिंग लैब और प्रस्तावित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी

प्रमुख डिजिटल परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाये ताकि नागरिकों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। आईटी ट्रेनिंग लैब सरकारी अधिकारियों को आधुनिक डिजिटल प्रशासन के अनुरूप



आवश्यक तकनीकी कौशल प्रदान

करेगी, जबकि एआई प्रशिक्षण उन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यावहारिक उपयोग, नवाचार और प्रशासनिक कार्यों में उसके प्रभावी इस्तेमाल से परिचित करायेगा।

इससे सरकारी कार्यप्रणाली अधिक दक्ष होगी, निर्णय प्रक्रिया मजबूत बनेगी और नागरिकों को मिलने वाली सेवाएं अधिक सरल, तेज और पारदर्शी होंगी।

उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली डिजिटल गवर्नेंस के अगले चरण का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक

संस्थागत और तकनीकी आधार तैयार कर रही है। उन्होंने कहा, 'आधुनिक एआई आईटी ट्रेनिंग लैब के माध्यम से सरकारी अधिकारियों की डिजिटल क्षमता को मजबूत करने और एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना से नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

हम ऐसा भविष्य उन्मुख डिजिटल इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, जो शासन व्यवस्था और नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुविधाजनक बनायेगा।

नशा मुक्त भारत अभियान देश में 23 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा

नयी दिल्ली, यूटर्न/ 08 जुलाई । केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का देशव्यापी नशा मुक्त भारत-अभियान (एनएमबीए) अब राष्ट्रव्यापी स्तर पर विस्तारित होते हुए 7.81 करोड़ से अधिक युवा, 5.24 करोड़ महिलाओं और 17 लाख शैक्षणिक संस्थानों सहित 23 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच चुका है। इसने आरंभ में 272 प्रभावित जिलों को लक्षित किया था। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने देश में मादक पदार्थों की लत से निपटने के लिए 15 अगस्त 2020 से नशा मुक्त भारत अभियान-एनएमबीए चला रखा है। इसमें सामूहिक कार्रवाई की अविलम्ब आवश्यकता को समझते हुए मंत्रालय, रोकथाम, मूल्यांकन, उपचार, पुनर्वास, उपचार उपरान्त देखभाल, जनसूचना प्रसार और सामुदायिक जागरूकता सहित विभिन्न पहल समन्वयित करता है। केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान स्वस्थ और अनुशासित युवाओं पर केंद्रित राष्ट्र निर्माण की प्रमुख पहल है।

शाह ने प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं और अप्रवासन प्रणाली की समीक्षा की

नयी दिल्ली, यूटर्न/ 08 जुलाई । केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापुर ने बुधवार को प्रमुख हवाई अड्डों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था एवं अप्रवासन प्रणाली की समीक्षा की। श्री शाह ने देश के सभी हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से स्वचालित एक्स-रे ट्रे प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दिये जिससे कि इस काम में लगे लोगों पर आने वाले खर्च को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि नये हवाई अड्डों में स्वचालित एक्स-रे ट्रे प्रणाली ही स्थापित करने के उचित मापदंड तय किये जायें। उन्होंने हवाई अड्डों में अंदर जाने के लिए प्रवेश लेन, चेक-इन काउंटर, सुरक्षा जांच लेन और अप्रवासन काउंटर के बीच पारस्परिक निर्भरता को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करने के निर्देश दिये, ताकि किसी भी 'टचपॉइंट' पर यात्रियों की भीड़ न हो और उन्हें असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डे के प्रत्येक टचपॉइंट पर समन्वित योजना तैयार की गयी है।

जीपीए के जरिए संपत्ति हस्तांतरण पर दिल्ली सरकार सख्त

नयी दिल्ली, यूटर्न/ 08 जुलाई । दिल्ली सरकार ने अचल संपत्तियों के पंजीकरण में स्टांप ड्यूटी की फजीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) के जरिए होने वाले संपत्ति लेन-देन की जांच को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर अब सभी सब-रजिस्ट्रार जीपीए दस्तावेजों की गहन जांच करेंगे और रक्त संबंधियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में होने वाले जीपीए मामलों को अनिवार्य रूप से 'क्लेक्टर ऑफ स्टांप' के पास भेजा जाएगा।

चार वर्ष में 32 हजार ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी : रेखा गुप्ता

» नयी दिल्ली, यूटर्न/ 08 जुलाई ।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि सरकार अगले चार वर्षों में दिल्ली में मौजूदा लगभग नौ हजार ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर करीब 32 हजार करने के लक्ष्य पर गंभीरता से जुटी है।

श्रीमती गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में नई ईवी नीति को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में स्पष्ट किया कि अगले चार वर्षों में दिल्ली में मौजूदा लगभग 9 हजार ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर करीब 32 हजार करने के लक्ष्य पर गंभीरता से जुटी है।

उन्होंने कहा कि इसके लिए बिजली आपूर्ति, उपयुक्त स्थानों की उपलब्धता और विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली को वास्तविक अर्थों में ईवी सिटी बनाने के लिए ऐसे आधुनिक चार्जिंग स्टेशन विकसित किये जायें, जहां बैठने की व्यवस्था, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों और अधिकांश स्टेशनों पर हर प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज किये जा सकें।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में फास्ट चार्जिंग तकनीक को प्राथमिकता दी जाये तथा वर्तमान में संचालित सभी स्लो



चार्जिंग स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से फास्ट चार्जिंग स्टेशनों में परिवर्तित किया जाये।

बैठक में चार्जिंग स्टेशनों के लिए उपयुक्त स्थानों की उपलब्धता पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दिल्ली मेट्रो की पार्किंग, नगर निगम के पार्किंग स्थल, मेट्रो के एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे उपलब्ध खाली स्थान, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) बाजारों के आसपास, प्रमुख मॉल, रेलवे स्टेशनों के बाहर, सरकारी परिसरों और बड़े व्यावसायिक क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की संभावनाओं पर प्राथमिकता से कार्य किया जाये ताकि लोगों को अपने घरों और कार्यस्थलों के निकट चार्जिंग सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर

चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए विभिन्न एजेंसियों का सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है।

इस दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर्स (ओईएम) के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

उन्होंने अधिकारियों से चार्जिंग स्टेशनों के लिए आवश्यक बिजली आपूर्ति, भविष्य में बढ़ने वाली मांग और उसके अनुरूप विद्युत अवसंरचना की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार केवल स्थान चुनने करने तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि इनके निर्बाध संचालन के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना भी उतना ही आवश्यक है।

ममता बनर्जी को बड़ा झटका ईडी ने फ्रीज किए टीएमसी के 3 अकाउंट

» कोलकाता, यूटर्न/ 08 जुलाई ।

पश्चिम बंगाल की सीएम रहीं ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। ईडी ने टीएमसी से जुड़े तीन अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। इन तीनों अकाउंट में 440 करोड़ रुपये जमा हैं। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की है। एजेंसी ने पार्टी के खातों के जरिए हुए कथित सिद्दाहस्पद लेनदेन और चार्टर्ड विमान के खर्चों की जांच के लिए कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी की।

दरअसल, ईडी ने टीएमसी के बैंक खातों से कथित हेरफेर कर 'एम्बेयर' विमान और 'अगस्ता वेस्टलैंड' हेलीकॉप्टर खरीदे जाने के मामले में बीते दिन कोलकाता में कई



जगहों पर छापेमारी की थी। अधिकारियों का कहना है कि कोलकाता में करीब 5 ठिकानों पर रेड की गई। इनमें 'केयरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज' के ठिकाने भी शामिल हैं। ये 'केयरवेल एविएशन' नाम से प्राइवेट जेट किराए पर देती है।

यूजीसी-नेट पेपर लीक पर गरमाई सियासत राहुल गांधी ने साधा केंद्र पर निशाना

» नयी दिल्ली, यूटर्न/ 08 जुलाई ।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यूजीसी-नेट परीक्षा के कथित पेपर लीक के गंभीर आरोपों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

श्री गांधी ने कहा कि नीट पेपर लीक के कुछ ही सप्ताह बाद अब यूजीसी-नेट परीक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जो देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर बड़ा संकट है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि परीक्षा से ठीक पहले 100 पन्नों की एक पीडीएफ प्रसारित हुई, जो प्रश्नपत्र तैयार करने से संबंधित थी और कथित तौर पर केवल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के पास उपलब्ध हो सकती थी।

उन्होंने दावा किया कि इस पीडीएफ के लगभग 90 प्रश्न समाजशास्त्र के वास्तविक



प्रश्नपत्र से मेल खाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यही प्रश्नपत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में 2.25 लाख रुपये में बेचा जा रहा था। साथ ही, इसी नेटवर्क द्वारा सीएसआईआर-नेट, एचटीईटी और एडीए जैसी आगामी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का दावा भी किया गया।

संक्षिप्त खबरें

बंगलामुखी मंदिर में दान के प्रबंधन पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश

आगर मालवा, यूटर्न/ 08 जुलाई । मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थित प्रसिद्ध माँ बंगलामुखी मंदिर नए विवाद के केंद्र में आ गया है, जहाँ दान और चढ़ावे के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद जिला प्रशासन ने उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े हालिया विवाद के बाद सामने आए मामले में, प्रशासन ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसे 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

केडीएमसी अस्पताल मारपीट: राउत ने दोषियों को अंडरवियर में घुमाने की मांग की

मुंबई, यूटर्न/ 08 जुलाई । कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (केडीएमसी) के एक अस्पताल में महिला डॉक्टरों और नर्सों पर कथित हमले को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान तेज हुआ है। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने घटना पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने मिथे गैंग के नाम से जाने वाले हमलावरों के लिए सख्त सजा की मांग की। राउत ने मुख्यमंत्री फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, कृपया अपने पास मौजूद गृह मंत्री के पद का सम्मान करें। उन्होंने सवाल उठाया कि कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाली महिला डॉक्टरों और नर्सों पर अस्पताल में घुसकर बेरहमी से पीटना क्या कानून का राज है? शिवसेना यूबीटी नेता राउत ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सभी दोषियों को हथकड़ी पहनाकर सिर्फ अंडरवियर और बनियान में सड़कों पर घुमाया जाए। हालांकि, शिवसेना के कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे, जिन पर हमले का आरोप है, ने इन आरोपों से इंकार किया है।

संक्षिप्त खबरें

गंगाजल न मिलने से नाराज, रेजिडेंट्स का प्रदर्शन

गाजियाबाद, यूटर्न/ 08 जुलाई। सिद्धार्थ विहार स्थित गंगा-यमुना हिंडन अपार्टमेंट में पिछले एक सप्ताह से गंगाजल आपूर्ति न होने से नाराज निवासियों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के संयोजक कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा कि जलनिगम के अनुसार पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके बावजूद आवास विकास परिषद अपार्टमेंट को उसके हिस्से का गंगाजल नहीं दे रहा है। इसी से निवासियों में आक्रोश है। पूर्व अध्यक्ष एन त्रिपाठी और देवेन्द्र कुमार ने निर्माण खंड-2 के अधिशासी अभियंता विकास गौतम को पत्र लिखकर उपलब्धता के अनुरूप गंगाजल आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। प्रदर्शन में एसएल वत्स, अरुण श्रीवास्तव, ललित शर्मा, केसी शर्मा, अजय वर्मा, शशि यादव, हिमांशी नौटियाल, शीला यादव, भावना सहित बड़ी संख्या में रेजिडेंट्स शामिल रहे।

फुटबॉल मारने का विरोध करने पर किशोर को पीटा

साहिबाबाद, यूटर्न/ 08 जुलाई। शालीमार गार्डन एक्सटेंशन एक निवासी सरिता श्रीवास्तव ने दो लोगों पर बेटे को फुटबॉल मारने और विरोध पर पिटाई का आरोप लगाया है। मामला 3 जुलाई का है, पुलिस ने सात जुलाई को मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस को दी तहरीर में सरिता श्रीवास्तव ने बताया कि शुक्रवार को उनका बेटा ऋषभ सोसायटी स्थित पार्क में ही दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। इस दौरान उसके एक दोस्त ने जानबूझकर फुटबॉल मार दी। जब बेटे ने इसका विरोध किया तो आरोपी और उसके साथी ने गाली-गलौज करते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया। प्रभारी एसीपी शालीमार गार्डन अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित और आरोपी दोनों आपस में दोस्त हैं।

वेयर हाउस से दो कर्मियों ने चुराए 20 मोबाइल फोन, प्राथमिकी दर्ज

साहिबाबाद, यूटर्न/ 08 जुलाई। लिंकरोड थानाक्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र साइट चार स्थित कोरियर कंपनी के वेयर हाउस से 20 मोबाइल फोन चोरी हो गए। चोरी का आरोप वेयर हाउस कर्मचारी हापुड़ निवासी अनुज कुमार और पीयूष कुमार पर लगाया गया है। वेयर हाउस सुपरवाइजर नंदग्राम निवासी मनोज गोस्वामी की तहरीर पर पुलिस ने 7 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। दर्ज मामले में मनोज गोस्वामी ने बताया कि वह कोरियर कंपनी के वेयर हाउस में कार्यरत हैं। तीन जुलाई को वेयर हाउस के अंदर रखे 20 मोबाइल फोन का एक बॉक्स चोरी हो गया।

जुलाई में मानसून में सुधार से राहत, कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178: शिवराज

नयी दिल्ली, यूटर्न/ 08 जुलाई।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि जून में 33 प्रतिशत कम बारिश के बाद जुलाई में स्थिति में सुधार आया है और अब यह कमी घटकर 24 प्रतिशत रह गयी है तथा हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गयी है।

श्री चौहान ने आज यहां उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में विशेष निगरानी रखी जा रही है।



उम्मीद है कि जुलाई में बारिश और रफतार पकड़ेगी, जिससे खरीफ बुवाई में तेजी आयेगी। कृषि मंत्री ने बताया कि फिलहाल 350.85 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई है, जो पिछले साल के

मुकाबले करीब 91.95 लाख हेक्टेयर कम है।

मानसून में देरी का असर सोयाबीन और कपास पर पड़ा है, लेकिन किसानों को मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम अवधि और कम पानी वाली फसलों की बुवाई की सलाह दी गयी है।

सरकार ने इस चुनौती के लिए पहले ही अप्रैल से तैयारी शुरू कर दी थी।

आईसीएआर के सहयोग से प्रभावित होने की संभावना वाले जिलों के लिए आपातकालीन योजना तैयार करके राज्यों के साथ साझा की गयी है। जून महीने में चलाये गये 'खेत बचाओ अभियान' के तहत 1.24 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किये गये और 80 लाख से ज्यादा किसानों तक सीधे पहुंच बनायी गयी।

श्री चौहान ने कहा कि बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए करीब 1.75 लाख

किंवदंती का राष्ट्रीय बीज भंडार तैयार रखा गया है, ताकि किसी भी स्थिति में बुवाई प्रभावित न हो।

इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड अभियान को तेज करते हुए 30 जून तक प्राप्त 1.14 लाख आवेदनों में से 94 हजार से अधिक को स्वीकृति दी जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं, ताकि किसी भी संभावित नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

श्री चौहान ने बताया कि अल नीनो की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निगरानी प्रणाली पूरी तरह सक्रिय है। अधिकारी लगातार मानसून, बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर नजर बनाये हुए हैं।

ई20 पेट्रोल पर छिड़ी रार, केजरीवाल ने मारुति, टॉयोटा और हीरो समेत 29 कंपनियों को लिखी चिट्ठी, जनता के बीच जाएंगे केजरीवाल

नई दिल्ली यूटर्न/ 08 जुलाई।

देशभर में ई20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर में जनता के बीच जाएंगे। वो इस 20 प्रतिशत एथनॉल वाले पेट्रोल पर जनता से राय लेंगे। केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि कल मैंने कहा था कि देश के सभी वहन निमाताओं को चिट्ठी लिखकर पूछूंगा कि क्या उनके पुराने वाहनों में ई20 ईंधन का इस्तेमाल किया जा सकता है? नुकसान होता है या नहीं? केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने तीन कंपनियों मारुति, टॉयोटा और हीरो को अलग से चिट्ठी लिखी है और 26 को अलग। इन तीनों ने सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नुकसान नहीं होता, 3-4 फीसदी ही माइलेज का नुकसान होता है तो इनसे पूछा है कि अगर किसी ग्राहक का 10-15 फीसदी माइलेज घटता है या इंजन को नुकसान पहुंचता है तो उसे कवर करेंगे? बाकी 26 वाहन निमाता कंपनियों से पूछा है कि क्या आपकी गाड़ियों में ई20 पेट्रोल से माइलेज या इंजन का नुकसान तो नहीं है, अगर ऐसा होता है तो उनको कौन कंपनसेशन देगा? ई20 प्यूल पर विवाद इस बात को लेकर है कि 2023 से पहले बनी ज्यादातर गाड़ियां ई10 के लिए बनी हैं। कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि ई20 भरने के बाद गाड़ी की माइलेज 2-6 प्रतिशत तक घट गई है। मतलब एक लीटर पेट्रोल से पहले जितना रन नहीं मिल रहा। ई20 में ज्यादा एथनॉल होने से रबर के पार्ट्स खराब हो सकते हैं। एआरआई की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। हालांकि, यह रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। उधर, सरकार का कहना है कि अब तक किसी गाड़ी में बड़ी खराबी का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि ई20 पेट्रोल को लेकर कई गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं।



बीटेक पानी पूरी वाली' बुलेट लेडी तापसी उपाध्याय का गीता कन्या विद्यालय में हुआ भव्य स्वागत

परमिंदर सिंह

कुरुक्षेत्र, यूटर्न/ 08 जुलाई। गीता कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज एक प्रेरणादायक अवसर रहा, जब देश की प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर, सोशल एंटरप्रेन्योर एवं हेल्थ एक्टिविस्ट तापसी उपाध्याय का विद्यालय परिवार द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर तापसी के दोनों भाई, संकुल प्रमुख व गीता निकेतन विद्या मंदिर, मोहन नगर के प्रधानाचार्य यशपाल वधवा, ग्रामीण शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष गुलशन ग्रोवर, बालिका शिक्षा प्रांत प्रभारी सरोज सैनी, गीता सह शिक्षा विद्यालय की प्रधानाचार्या राजकुमारी, विद्यालय की पूर्व आचार्या व मेजर नितिन बाली गीता निकेतन विद्या मंदिर, सुंदरपुर की प्रधानाचार्या मंजुला, मेजर नितिन बाली गीता निकेतन विद्या मंदिर विद्यालय की प्रबंध समिति की महिला उपाध्यक्षा ममता सूद, गीता सह शिक्षा विद्यालय की प्रबंध समिति की महिला सदस्य किरण गर्ग व उत्तर क्षेत्र संस्कृति बोध परियोजना के प्रमुख अनिल कुलश्रेष्ठ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदा के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर वंदना के साथ किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्या सुमन बाला ने आए हुए अतिथियों का परिचय करवाया व तापसी को पुष्प माला पहनाकर एवं उत्तरीय तथा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि तापसी उपाध्याय कंप्यूटर साइंस में बीटेक और बीए (लैण्ड) की डिग्री प्राप्त कर वर्तमान में अपनी फ्लूइड बाइक से 'ओबेसिटी मुक्त



भारत इंडिया टूर' पर हैं। अब तक वे 20 राज्यों, 200 से अधिक शहरों में लगभग 600 अभियानों के जरिए 5 लाख से अधिक युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर चुकी हैं। सरोज सैनी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब को आगे बढ़ना है। हमें अपने अधिकारों को जानते हुए कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। नदी से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चियों को मयार्दा में रहना चाहिए व समाज का सम्मान करना चाहिए। गुलशन ग्रोवर ने कहा कि एक महिला पूरे समाज को सशक्त कर सकती है पर उसके लिए पहले उसे स्वयं सशक्त होना पड़ेगा। कोई भी काम छोटा व बड़ा नहीं होता, एक छोटे से काम से भी हम अपना बड़ा नाम कमा सकते हैं, उसके लिए हमें अपने गुरुओं व माता-पिता से मार्गदर्शन लेना होगा व ऊंचाइयों की सीढ़ियां पर चढ़ना होगा।

इस अवसर पर तापसी ने उपस्थित सभी लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने व चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हमें करियर के साथ कैरेक्टर और सेवा का भाव रखना चाहिए। स्वस्थ भारत का निर्माण करना ही हमारा लक्ष्य है, इसके लिए उन्होंने पांच मूल मंत्र दिए जिसमें स्वस्थ भोजन, व्यायाम व योग, पर्यावरण की रक्षा, परिवार के साथ समय बिताना, व समाज में नाम कमाना सम्मिलित है। उन्होंने बच्चों को जंक फूड से बचने, मोटापे के खतरों और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, 'आपका स्वास्थ्य ही आपका असली धन है। पढ़ाई के साथ फिट रहना भी जरूरी है। अंत में संकुल प्रमुख यशपाल वधवा ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। 'हमारा मिशन-स्वस्थ भारत' के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

बारिश का पानी भरने पर पड़ोसियों ने घर में घुसकर युवक को पीटा

लोनी, यूटर्न/ 08 जुलाई। न्यू विकास नगर कॉलोनी की गली में पानी भरने पर हुए विवाद के बाद पड़ोसियों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। कॉलोनी निवासी दिग्विजय ने बताया कि पांच जुलाई को बारिश हो रही थी और पानी गली में भर गया। आरोप है कि पड़ोसी विजय और उसके बेटे प्रवीण व मनोज ने गली में बारिश के पानी भरने पर गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर विजय अपने दोनों बेटों के साथ लाठी डंडा और लोहे का सरिया लेकर उनके घर में घुस गया और मारपीट की।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शहरों की तर्ज पर कर रहे हैं गांवों का विकास : सुभाष सुधा

पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने गांव आलमपुर में पेयजल पाइपलाइन बदलने के कार्य के रोड़ चौपाल के नवनिर्माण के कार्य की भी आधारशिला रखी

अश्विनी वालिया

कुरुक्षेत्र, यूटर्न/ 08 जुलाई। हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गांवों का विकास शहरों की तर्ज पर कर रहे हैं। गांवों में शहरों जैसी सभी सुविधाएं सुधैया करवाई जा रही है। ग्रामीणों के

लिए सैर करने के लिए पार्क, व्यामशालाएं, कम्प्यूनिटी सेंटर बनाए जा रहे हैं। पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा आज थानेसर विधानसभा क्षेत्र के गांव आलमपुर में जन-जीवन (जे.जे.) योजना के अंतर्गत पुरानी एवं क्षतिग्रस्त एसी/पीवीसी पेयजल पाइपलाइन को बदलने के कार्य का विधिवत शुभारंभ किया।

पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। गांव आलमपुर में पुरानी और जर्जर पेयजल



पाइपलाइन के कारण लोगों को आने वाली समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से यह कार्य कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को बेहतर पेयजल सुविधा मिल सकेगी।

उन्होंने कहा कि गांव आलमपुर में पेयजल पाइपलाइन बदलने के पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 24.66 लाख रुपये की लागत आ रही है। इसी कड़ी में आज सरकारी स्कूल से लेकर दयालचंद के घर तक लगभग 468 मीटर लंबी नई पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया गया, जिस पर लगभग 4.50 लाख रुपये की लागत आएगी।

उन्होंने रोड़ चौपाल के नवनिर्माण के कार्य की भी आधारशिला रखी जिस पर लगभग 10.50 लाख का खर्च आयेगा।

पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है और क्षेत्र के प्रत्येक गांव में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर अंकित मैहला, रजनीश पूर्व सरपंच, संजीव आलमपुर, बिट्टु, साहिल, दिलबाग, दयालचंद मंडी प्रधान व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

‘देश के प्रथम 20,000 योग प्रेरकों में अत्वल रहीं 3 हरियाणा गर्ल्स बटालियन की: मेजर आकांक्षा पांडे’

» राजेश सलूजा

हरियाणा, यूटर्न/08 जुलाई: तृतीय हरियाणा गर्ल्स बटालियन एनसीसी, हिसार की प्रशासनिक अधिकारी मेजर आकांक्षा पांडे ने हर घर योग अभियाना एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार योग को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान में मेजर आकांक्षा पांडे ने अपने समर्पण और

निरंतर प्रयासों से 5636 नागरिकों को नियमित योगाभ्यास अपनाने हेतु प्रेरित किया। उनके अनुकरणीय कार्यों के लिए उन्हें हबिल्ड (HABUILD) द्वारा प्रशंसा पत्र (Certificate of Appreciation) प्रदान कर सम्मानित किया गया।

यह अभियान पूरे देश में चलाया गया, जिसमें देश के लाखों योग प्रेरकों ने योग प्रोत्साहन के लिए अथक प्रयास और भागीदारी की। कड़ी प्रतिस्पर्धा के पश्चात मेजर आकांक्षा पांडे ने इन सभी प्रेरकों के मध्य प्रथम स्थान प्राप्त



किया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने न केवल तृतीय हरियाणा गर्ल्स बटालियन एनसीसी, हिसार का मान बढ़ाया, बल्कि एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर रोहतक को भी गौरवान्वित किया। मेजर आकांक्षा पांडे के इस प्रयास से समाज में स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। इस अवसर पर तृतीय हरियाणा गर्ल्स बटालियन, हिसार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ज्ञान प्रकाश पाण्डेय ने मेजर आकांक्षा पांडे को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, मेजर आकांक्षा की

यह उपलब्धि एनसीसी कैडेट्स एवं प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। हमें विश्वास है कि वे भविष्य में भी इसी लगन से राष्ट्रहित और समाज सेवा में अपना योगदान देते रहेंगे। इस उपलब्धि पर पी.एम. श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बालक जिला हिसार के प्रधानाचार्य रमेश यादव जी एवं पूरा विद्यालय परिवार ने बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी तथा ग्राम पंचायत बालक जिला हिसार के तरफ से सरपंच प्रतिनिधि कृष्ण रेड्डी ने भी इस अवसर पर बधाई दी।

हरियाणा R&V स्वचाइन NCC ने कंबाईड एनुअल ट्रेनिंग कैंप (CATC-180) शुरू किया



» हरियाणा, यूटर्न/ 08 जुलाई ।

हरियाणा R&V स्वचाइन NCC ने आज कैंप कमांडेंट कर्नल विनीत बुटोला की कमान में अपना कंबाईड एनुअल ट्रेनिंग कैंप (CATC-180) शुरू किया। इस कैंप में अलग-अलग स्कूलों और कॉलेजों के NCC कैडेट्स को एक साथ लाया गया है, जिसका मकसद अनुशासन, नेतृत्व, आत्मविश्वास, टीमवर्क और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करना है।

अपने उद्घाटन भाषण में, कर्नल विनीत बुटोला ने कैडेट्स, एसोसिएट NCC ऑफिसर्स (ANOs), परमानेंट इंस्ट्रक्टर (PI) स्टाफ, सिविलियन स्टाफ और खास मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कैंप को सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए एक बेहतरीन मंच बताया और कैडेट्स से ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाले मौकों का भरपूर फायदा उठाने को कहा।

NCC के आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन पर जोर देते हुए, कर्नल बुटोला ने कहा कि अनुशासन सफलता की नींव है, जबकि एकता हर चुनौती से पार पाने की ताकत देती है। उन्होंने कैडेट्स को कैंप के दौरान और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। कैंप की योजना बहुत

सावधानी से बनाई गई है ताकि ड्रिल, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, मैप रीडिंग, शारीरिक फिटनेस, आपदा प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, सामुदायिक सेवा और नेतृत्व विकास में व्यापक ट्रेनिंग दी जा सके। इसके अलावा, जाने-माने गेस्ट स्पीकर्स समकालीन और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर लेक्चर देंगे, जिनमें स्टेम सेल डोनेशन, साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता, परमाणु ऊर्जा, सुरक्षा और वैज्ञानिक विकास, अंगदान और अग्नि सुरक्षा शामिल हैं। इन सेशन का मकसद कैडेट्स की जागरूकता बढ़ाना और उन्हें जरूरी जानकारी और जीवन कौशल से लैस करना है।

अनुशासन और सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए, कर्नल बुटोला ने कैडेट्स को निर्देश दिया कि वे कैंप के दौरान समय की पाबंदी और व्यक्तिगत आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। उन्होंने दोहराया कि किसी भी ट्रेनिंग गतिविधि, खासकर हथियार संभालने, बाधा पार करने की ट्रेनिंग और शारीरिक व्यायाम के दौरान सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

कैंप कमांडेंट ने कैडेट्स को याद दिलाया कि कैंप का मकसद सिर्फ प्रतियोगिताएं जीतना या सर्टिफिकेट हासिल करना नहीं है, बल्कि चरित्र, सहनशक्ति, नेतृत्व के गुण, आत्मनिर्भरता और टीमवर्क की भावना विकसित करना है।

क्रैच वर्क्स एंड हेल्पर्स यूनियन संबंधित सीटू का तीसरा सम्मेलन आयोजित

» निर्मल सिंह विक्र

पानीपत, यूटर्न 8 जुलाई । सीटू जिला कार्यालय क्रांतिकारी शिववर्मा स्मारक भवन, गीता कॉलोनी पानीपत में क्रैच वर्क्स एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा संबंधित सीटू का तीसरा पानीपत जिला सम्मेलन पूनम जिला प्रधान की अध्यक्षता में किया गया। जिला सचिव नूतन ने पिछले तीन वर्ष की रिपोर्ट रखते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर सरकार से संघर्ष किया। वर्तमान समय में भी संघर्ष जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगा।



*सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीटू राज्य सचिव सुनील दत्त ने कहा कि क्रैच वर्क्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने हरियाणा के अंदर कम

संख्या में होते हुए भी अपने रोजगार को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ वर्षों तक लंबे संघर्ष के बाद जीत हासिल की। वर्तमान समय में यूनियन की मांग

है कि क्रैच वर्क्स एंड हेल्पर्स यूनियन में कार्यरत सभी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नाम मिले तब तक न्यूनतम वेतन 30000 दिए जाएं। इसके अलावा ईएसआई, पीएफ, सामाजिक सुरक्षा, रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष किया जाए, रिटायरमेंट बनिफिट्स 5 लाख रुपए दिया जाए। सीटू यूनियन की आंदोलन का समर्थन करती है।

*सर्वसम्मति से जिला कमेटी का चुनाव किया गया जिसमें प्रधान नूतन, सचिव पूनम, कोषाध्यक्ष ललिता, अनीता, सुशीला, राजबाला, मुकेश को सदस्य चुना गया।

15 अगस्त तक मेरा युवा भारत पोर्टल पर सघन पंजीकरण एवं जन-जागरूकता अभियान प्रारम्भ

» अश्विनी वालिया

कुरुक्षेत्र, यूटर्न/ 08 जुलाई । उप निदेशक सुरमयी शर्मा ने कहा कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के विभाग मेरा युवा भारत द्वारा 15 अगस्त 2026 तक पूरे देश में सघन पंजीकरण एवं जन-जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को मेरा युवा भारत पोर्टल से जोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 5 करोड़ युवाओं के पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है।

उन्होंने कहा कि इस अभियान में कुरुक्षेत्र जिले के सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों तथा अन्य शिक्षण एवं सामाजिक संस्थाओं में विशेष पंजीकरण शिविर, जन जागरूकता कार्यक्रम, संवाद गोष्ठियां तथा प्रचार-प्रसार गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक



युवाओं को पोर्टल पर पंजीकरण कराने के साथ साथ उन्हें राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के प्रति भी जागरूक करेंगे।

उप निदेशक सुरमयी शर्मा ने कहा कि मेरा युवा भारत केवल एक पंजीकरण मंच नहीं है, बल्कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने वाला एक सशक्त राष्ट्रीय माध्यम है। इसके माध्यम से युवाओं को समय-समय पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम,

उप निदेशक सुरमयी शर्मा ने कहा कि मेरा युवा भारत केवल एक पंजीकरण मंच नहीं है, बल्कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने वाला एक सशक्त राष्ट्रीय माध्यम है।

उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान प्रत्येक स्वयंसेवक, माई भारत नामित अधिकारी एवं माई भारत स्टूडेंट एम्बेसडर अपने पंजीकरण रेफरल कोड के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को पोर्टल से जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे।

वजट क्वेस्ट अभियान, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, कौशल विकास गतिविधियां, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, रक्तदान, सामुदायिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, जन जागरूकता अभियान तथा अन्य अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागिता

का अवसर प्राप्त होता है। विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ संवाद करने जैसे विशेष अवसर भी प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान प्रत्येक स्वयंसेवक, माई भारत नामित अधिकारी एवं माई भारत स्टूडेंट एम्बेसडर अपने पंजीकरण रेफरल कोड के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को पोर्टल से जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उप निदेशक ने जिला के सभी महाविद्यालयों, राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, युवा संगठनों तथा 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के सभी युवाओं से इस अभियान में सक्रिय सहभागिता करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक युवा स्वयं पंजीकरण करने के साथ-साथ अपने मित्रों, सहपाठियों, परिवार के पात्र सदस्यों तथा अपने आसपास के अन्य युवाओं को भी मेरा युवा भारत पोर्टल से जोड़ने का संकल्प ले।

रेडक्रॉस के तीन दिवसीय प्रशिक्षण का समापन, एनएफएल कर्मचारियों ने सीखे जीवन रक्षक प्राथमिक उपचार

आपदा और दुर्घटना में तुरंत मदद को तैयार होंगे कर्मचारी, व्यवहारिक प्रशिक्षण से बढ़ा आत्मविश्वास

» निर्मल सिंह विक्र

पानीपत, यूटर्न/ 08 जुलाई । औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड) में आयोजित तीन दिवसीय व्यवसायिक प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम का बुधवार को समापन हुआ।

अंतिम दिन जिला कल्चर

कोऑर्डिनेटर एवं फर्स्ट एड लेक्चरर संदीप रत्नेवाल ने प्रतिभागियों को विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन रक्षक प्राथमिक उपचार की व्यवहारिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद अस्पताल पहुंचने से पहले दिया गया सही प्राथमिक उपचार कई बार मरीज की जान बचा सकता है। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी के लिए प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान बेहद आवश्यक है।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को बेहोशी की स्थिति में मरीज की देखभाल, रिकवरी पोजिशन, फ्रेक्चर एवं रीढ़ की हड्डी की चोट में सुरक्षित तरीके से मरीज को संभालने, सांप व



कुत्ते के काटने, आग, गर्म तरल पदार्थ, रासायनिक एवं विद्युत जलन, गले में

वस्तु फंसने (चोकिंग), धुएँ या जहरीली गैस से दम घुटने, स्ट्रोक तथा विषाक्तता जैसी आपात स्थितियों में अपनाए जाने वाले प्राथमिक उपचार की विस्तृत जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण को पूरी तरह व्यवहारिक बनाते हुए प्रतिभागियों से प्रत्येक तकनीक का अभ्यास भी कराया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में घबराने के बजाय सही निर्णय लेना, मरीज की स्थिति का आकलन करना और समय पर प्राथमिक उपचार देना ही एक प्रशिक्षित फर्स्ट एडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य मरीज की जान बचाना, उसकी स्थिति को गंभीर होने से

रोकना और चिकित्सकीय सहायता मिलने तक उसे सुरक्षित रखना है।

समापन अवसर पर एनएफएल प्रबंधन ने जिला रेडक्रॉस सोसायटी और प्रशिक्षक संदीप रत्नेवाल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण औद्योगिक संस्थानों में सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने के साथ-साथ कर्मचारियों में मानव सेवा की भावना भी विकसित करते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों ने इसे अत्यंत उपयोगी और जीवन रक्षक बताया है। कहा कि अब वे किसी भी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में अधिक आत्मविश्वास के साथ जरूरतमंदों की सहायता कर सकेंगे।

चिंतन-मनन: विवेक ही धर्म है

युग के आदि में मनुष्य भी जंगली था। जब से मनुष्य ने विकास करना शुरू किया, उसकी आवश्यकताएं बढ़ गईं। आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से समस्या ने जन्म लिया। समस्या सामने आई तब समाधान की बात सोची गई। समाधान के स्तर दो थे- पदार्थ-जगत, मनो-जगत। प्रथम स्तर पर पदार्थ के सुनियोजित उत्पादन और उनकी व्यवस्था को आकार मिला। दूसरा स्तर मानसिक था। इस जगत की समस्याएं थी अपरिमाजित वृत्तियां, असंतुलन और तनाव। इन समस्याओं को समाहित करने के लिए धर्म की खोज हुई। धर्म का अर्थ है पारंपरिक मूल्य-मानकों से परे हटकर मनुष्य को सत्य की दिशा में अग्रसर करना। जब तक धर्म अपने इस परिवेश में रहता है, तब तक वह रूढ़ नहीं हो सकता। पर उद्देश्य की विस्मृति के साथ ही उसमें रूढ़ता आ जाती है। रूढ़ धर्म को व्यक्ति अपने जीवत संदर्भ से काटकर परलोक के साथ जोड़ देता है। बस यहीं से धर्म में विकृति का प्रवेश होने लगता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि धर्म का संबंध हमारी हर सांस से होना चाहिए। ऐसा वे ही व्यक्ति कर सकते हैं जो अपने जीवन की सतह पर दौड़-धूप कर रहे हैं। या फिर यह उन लोगों का काम है जो जीवन की गहराइयों में उतरकर अध्यात्म के प्रति समर्पित हो जाते हैं। जीवन की सतह पर जीने वाले व्यक्ति धर्म की गहराई में नहीं उतर सकते, किंतु अध्यात्म के प्रयोक्ता की दृष्टि से वह गहराई छिपी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति उतनी गहराई में उतरे, उन्हें धर्म की विकृतियों का बोध हुआ। जो धर्म मन को समाधान देने वाला था, वह स्वयं समस्या बनकर उभर गया। इस दृष्टि से उसमें संशोधन व परिवर्तन की अपेक्षा अनुभव हुई। अनुभव उसी आवश्यकता का आविष्कार है। यदि धर्म एक समस्या बनकर सामने नहीं आता तो उसे अनुभव के रूप में प्रस्तुति देने का कोई अर्थ ही नहीं था। अनुभव धर्म के साथ विवेक की अपरिहार्यता पर बल देता है। आगम की भाषा में विवेक ही धर्म है।

ऑपरेशन 'ब्लॉक कॉकरोच' नाकाम



संदीप शर्मा

दिल्ली हाई कोर्ट का वह फैसला, जिसमें व्यंग्य करने वाले हैंडल कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का एक्स अकाउंट बहाल करने का निर्देश दिया गया, किसी एक गुमनाम सोशल मीडिया पेज की जीत से कहीं ज्यादा है। यह उस सिद्धांत की अहम पुष्टि है जो हर लोकतंत्र की बुनियाद में है: सरकारों को आलोचना, मजाक और यहाँ तक कि बेअदबी को भी बर्दाश्त करने

में सक्षम होना चाहिए। जनता के बीच होने वाली बातचीत में राजनीतिक व्यंग्य की हमेशा एक खास जगह रही है। सोशल मीडिया के आने से बहुत पहले भी, कार्टून, व्यंग्य-लेख और पैरोडी कॉलम शासकों की कमियों को उजागर करके और सत्ता के रुतबे को कम करके उन्हें जवाबदेह बनाते थे। लोकतंत्र तब फलते-फूलते हैं जब नेता खुद पर हँस सकें या कम से कम, उन लोगों की आवाज दबाने के लालच से बच सकें जो उन पर हँसते हैं। सीजेपी का अकाउंट ब्लॉक करने से जुड़ा विवाद परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है। अगर सरकार की कार्रवाई से कोई व्यंग्य वाला अकाउंट रातों-रात गायब हो सकता है, तो यह उन हजारों आम नागरिकों को क्या संदेश देता है जो राजनीति पर टिप्पणी करने के लिए हास्य का सहारा लेते हैं? इसका असर सिर्फ एक अकाउंट तक सीमित नहीं रहता। मनमाने ढंग से अकाउंट हटाने का डर लोगों को खुद पर रोक लगाने (सेल्फ-सेंसरशिप) के लिए उकसाता है, जो अक्सर सीधे सेंसरशिप से ज्यादा असरदार होता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और उससे जुड़े नियम सरकार को कुछ खास हालात में, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या संप्रभुता के लिए खतरा होने पर ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार देते हैं। ये अधिकार खास मामलों में जरूरी हैं। हालाँकि, खास अधिकारों के लिए खास संयम की भी जरूरत होती है। इनका इस्तेमाल सरकारों या सरकारी अधिकारियों को शर्मिंदगी, आलोचना या मजाक से बचाने के लिए नहीं किया जा सकता। आपत्तिजनक बात और गैर-कानूनी बात के बीच का फर्क बहुत जरूरी है। व्यंग्य अक्सर जान-बूझकर बढ़ा-चढ़ाकर, उकसाने वाला और असहज करने वाला बनाया जाता है। इसका मकसद तथ्य बताना नहीं, बल्कि कटाक्ष और बेतुकेपन के जरिए सोचने पर मजबूर करना होता है। पैरोडी को गलत जानकारी (मिसइन्फॉर्मेशन) समझना या मजाक को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा मानना राजनीतिक व्यंग्य की असल प्रकृति को गलत समझना है। दिल्ली हाई कोर्ट का दखल एक और उतने ही अहम सिद्धांत को मजबूत करता है: अभिव्यक्ति की आजादी पर असर डालने वाले सरकारी फैसलों की न्यायिक जाँच होनी चाहिए। जब डिजिटल प्लेटफॉर्म या व्यक्तिगत अकाउंट पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, तो पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है। बिना ज्यादा स्पष्टीकरण के गुप्त आदेश जनता का भरोसा कम करते हैं और नागरिकों के मन में यह सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या कंटेंट मॉडरेशन कानून के तहत हो रहा है या राजनीतिक सुविधा के लिए। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यंग्य को पूरी छूट मिली हुई है। मानहानि, हिंसा के लिए उकसाना, नफरत फैलाने वाली बातें (हेट स्पीच) और जान-बूझकर गलत जानकारी फैलाना कानूनी दायरे में आते हैं। लेकिन पाबंदियाँ उचित, सोच-समझकर तय की गईं और ठोस वजहों पर आधारित होनी चाहिए। लोकतंत्र सेंसरशिप की सीमा कम करने से मजबूत नहीं होते; वे ज्यादा बोलने की आजादी देने से मजबूत होते हैं, न कि कम बोलने की।

भरत तिवारी एनकाउंटर कानून, राजनीति और बिहार की चुनावी सरगर्मी

कुमार कृष्णन

बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच कानून-व्यवस्था का प्रश्न एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु ने इस बहस को और तीखा कर दिया है। यह मामला अब केवल एक पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सत्ता पक्ष, विपक्ष और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के भीतर भी अलग-अलग प्रतिक्रियाओं का कारण बन गया है। विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ कानून-व्यवस्था एक बार फिर राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय बनती दिखाई दे रही है। भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु ने इसी बहस को नई दिशा दे दी है।

यह मामला अब केवल एक पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सत्ता पक्ष, विपक्ष और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के भीतर भी अलग-अलग प्रतिक्रियाओं का कारण बन गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी पुलिस मुठभेड़ का मूल्यांकन दो स्तरों पर होता है। पहला, क्या पुलिस ने कानून के अनुरूप कार्रवाई की? दूसरा, क्या पूरी घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हुई? यदि इन दोनों प्रश्नों के स्पष्ट और विश्वसनीय उत्तर नहीं मिलते, तो स्वाभाविक रूप से संदेह, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और जनचर्चा का दौर शुरू हो जाता है। भोजपुर की घटना भी इसी मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है।

इस पूरे घटनाक्रम को सबसे अधिक राजनीतिक महत्व तब मिला, जब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भरत तिवारी के परिजनों से मिलने उनके गांव पहुंचे। उन्होंने प्रथम दृष्टया पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मामला पुलिस के ओवर रिस्पॉन्स जैसा प्रतीत होता है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर भी प्रश्न उठाए और कहा कि यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही या साजिश सामने आती है तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भरत भूषण तिवारी गंगा कटाव से विस्थापित परिवारों की समस्याओं को लगातार उठाते रहे थे और इस कारण स्थानीय प्रशासन उनसे नाराज था। किसी मंत्री का ऐसा बयान सामान्य प्रशासनिक टिप्पणी नहीं माना जाता। सरकार का सदस्य जब पुलिस कार्रवाई पर सार्वजनिक रूप से प्रश्न उठाता है, तो उसका राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व स्वतः बढ़ जाता है। इससे यह संदेश भी जाता है कि सरकार के भीतर ही घटना को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण



मौजूद हैं। हालांकि, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसी टिप्पणियाँ अंतिम निष्कर्ष नहीं होतीं; किसी भी घटना का सत्य विधिवत जांच के बाद ही स्थापित होता है। इसी बीच जनता दल (यूनाइटेड) ने अशोक चौधरी के बयान से स्वयं को अलग कर लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट कहा कि यह अशोक चौधरी की व्यक्तिगत राय है, न कि पार्टी या सरकार का आधिकारिक दृष्टिकोण। उन्होंने यह भी कहा कि भरत तिवारी के घर उनका दौरा निजी था और सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को अपने वक्तव्यों में संयम और सावधानी बरतनी चाहिए।

यहीं से यह प्रकरण केवल पुलिस कार्रवाई का नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेशों का भी विषय बन गया। एक ओर सरकार के एक मंत्री निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और पुलिस कार्रवाई पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी ही पार्टी उस बयान को व्यक्तिगत राय बताकर उससे दूरी बना रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार के भीतर इस विषय पर एकरूपता नहीं है।

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अन्य घटकों के भीतर भी इस मुद्दे पर विभिन्न स्वर सुनाई दे रहे हैं। कुछ नेताओं ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया है, जबकि कुछ ने जांच पूरी होने तक संयम बरतने की बात कही है। लोकतांत्रिक राजनीति में मतभेद असामान्य नहीं होते, लेकिन चुनावी समय में ऐसे मतभेद अधिक चर्चा का विषय बन जाते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव राजनीतिक संदेश और जनधारणा दोनों पर पड़ता है। इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी वही है, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज में

होना चाहिए—क्या घटना की निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच होगी? यदि पुलिस की कार्रवाई कानूनसम्मत थी, तो जांच उसे स्पष्ट करेगी। यदि कहीं प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ या किसी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई, तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। कानून का शासन इसी संतुलन पर आधारित होता है कि न तो अपराध पर पर्दा डाला जाए और न ही पुलिस को कानून से ऊपर माना जाए।

इसी कारण भरत तिवारी प्रकरण अब बिहार की राजनीति में एक ऐसे मुद्दे के रूप में उभर रहा है, जहां कानून, प्रशासन और चुनावी राजनीति एक-दूसरे से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और राजनीतिक दलों की रणनीति यह तय करेगी कि यह मामला केवल एक स्थानीय घटना बनकर रह जाएगा या राज्य की व्यापक चुनावी बहस का हिस्सा बनेगा। भरत भूषण तिवारी प्रकरण ने बिहार में एक बार फिर उस बहस को जीवित कर दिया है, जो हर पुलिस मुठभेड़ के बाद सामने आती है—क्या कानून के शासन में न्याय का अंतिम निर्णय पुलिस की गोली से होगा या विधिक प्रक्रिया से? लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत यही है कि अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, दोष और दंड का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही होना चाहिए। दूसरी ओर, पुलिस का दायित्व कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आवश्यक परिस्थितियों में बल प्रयोग करना भी है। यही कारण है कि किसी भी मुठभेड़ की वैधता का निर्धारण तथ्यों, साक्ष्यों और निष्पक्ष जांच के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक दावों या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के आधार पर।

बचपन की असुरक्षा और समाज की विफलता

कुमार कृष्णन

श्रीगंगानगर की घटना से उदते सवाल

राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक तेरह वर्षीय छात्रा के साथ कथित सामूहिक यौन उत्पीड़न का मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं है। यह उस सामाजिक संकट का संकेत है, जिसकी आहत वर्षों से सुनाई दे रही है, लेकिन जिसे हम हर नई घटना के बाद कुछ दिनों के आक्रोश में भुला देते हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार एक नाबालिग छात्रा को कई दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ गंभीर अपराध किए जाने के आरोप हैं। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। न्यायालय का अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुँचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर उस प्रश्न को हमारे सामने खड़ा कर दिया है, जिससे बचना अब संभव नहीं—क्या भारत अपने बच्चों, विशेषकर अपनी बेटियों, को सुरक्षित बचपन दे पा रहा है?

हर बार जब ऐसी कोई घटना सामने आती है, तो हमारा सार्वजनिक विमर्श लगभग एक जैसा होता है। राजनीतिक बयान आते हैं, सोशल मीडिया पर आक्रोश उमड़ता है, कठोर दंड की मांग उठती है और कुछ दिनों



बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन अपराध सामान्य नहीं होते। वे समाज की गहराइयों में मौजूद उन विकृतियों का परिणाम होते हैं, जिन्हें हम लंबे समय तक अनदेखा करते रहते हैं। इसलिए श्रीगंगानगर की घटना को केवल पुलिस कार्रवाई या अदालत की प्रक्रिया तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। यह हमारे सामाजिक चरित्र, नैतिक शिक्षा, प्रशासनिक सतर्कता और लोकतांत्रिक संवेदनशीलता की सामूहिक परीक्षा है। भारत में बाल यौन हिंसा का संकट नया नहीं है। पिछले डेढ़ दशक में ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग बढ़ी है। इसका एक कारण यह भी है कि बच्चों के यौन शोषण को लेकर समाज में पहले की तुलना में अधिक जागरूकता आई है और पॉक्सो कानून के लागू होने के बाद शिकायत दर्ज कराने का रास्ता अपेक्षाकृत स्पष्ट

हुआ है। लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध आज भी भयावह स्तर पर मौजूद हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े लगातार बताते हैं कि हर वर्ष हजारों बच्चे यौन हिंसा का शिकार होते हैं। इनमें अधिकांश पीड़ित बच्चियाँ होती हैं और बड़ी संख्या में उनकी आयु किशोरावस्था से भी कम होती है।

इन आंकड़ों का सबसे भयावह पक्ष यह नहीं कि अपराध बढ़ रहे हैं, बल्कि यह है कि अधिकांश मामलों में अपराधी कोई अजनबी नहीं होता। वह परिवार का परिचित, पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र या ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर बच्चा और उसका परिवार भरोसा करता है। यानी खतरा बाहर से कम और भीतर से अधिक है। यह तथ्य हमारी पारंपरिक सुरक्षा की समझ को बदल देता है। हम बच्चों को अनजान लोगों से सावधान रहना सिखाते हैं, लेकिन क्या उन्हें यह भी सिखाते हैं कि किसी परिचित द्वारा अनुचित व्यवहार होने पर वे बिना भय अपनी बात कह सकें? समाजशास्त्री लंबे समय से यह कहते रहे हैं कि किसी भी समाज में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं होती। वह उस सामाजिक सोच का परिणाम होती है जिसमें शक्ति, प्रभुत्व और स्त्री के प्रति असमान दृष्टि गहराई से मौजूद होती है।

मोबाइल रिचार्ज में भारी बढ़ोतरी तय, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

रिचार्ज प्लान 12 से 15 प्रतिशत तक महंगे हो सकते

» मुंबई, यूटर्न/ 08 जुलाई ।

भारतीय मोबाइल उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला है। जल्द ही आपके मासिक या वार्षिक रिचार्ज प्लान 12 से 15 प्रतिशत तक महंगे हो सकते हैं, जिससे आपकी जेब पर सीधा बोझ पड़ेगा। ताजा रिपोर्टों के अनुसार, देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने



औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता (एआरपीयू) में सुधार लाने और 5जी नेटवर्क पर किए बड़े निवेश की भरपाई की तैयारी में हैं। पिछले टैरिफ बढ़ोतरी के झटके से उपभोक्ता अभी उबर भी नहीं सके थे कि यह दूसरी बड़ी वृद्धि सामने आने वाली है।

टेलीकॉम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले तीन से चार महीनों के भीतर यह बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बाजार में अब केवल 3+1 खिलाड़ी होने के कारण, कंपनियों के लिए कीमतें बढ़ाना आसान हो गया है और प्रतिस्पर्धा का दबाव कम हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाली तिमाही में सभी निजी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के एआरपीयू में 1-1.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। इसका मुख्य कारण ग्राहकों का 2जी से 4जी और 5जी नेटवर्क पर अपग्रेड होना, पोस्टपेड ग्राहकों की बढ़ती संख्या और डेटा उपयोग में लगातार वृद्धि है। रिलायंस जियो और भारती

एयरटेल अपने सब्सक्राइबर मार्केट शेयर में लगातार इजाफा कर रही हैं, जबकि दोनों ही कंपनियाँ देश के 90 प्रतिशत से अधिक जिलों में 5जी सेवाएं शुरू कर चुकी हैं और अपने नेटवर्क में अधिक 5जी डिवाइस जोड़ने पर काम कर रही हैं। वोडाफोन आइडिया भी लगभग 100 शहरों में अपनी 5जी सेवा का विस्तार कर रहा है। डेटा के बढ़ते इस्तेमाल को देखकर टेलीकॉम कंपनियों को लगता है कि कीमतों में बढ़ोतरी का सही समय है। कुल मिलाकर, मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द ही अपने कम्युनिकेशन खर्चों में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार रहना होगा।

संक्षिप्त खबरें सोने और चांदी के भावों में आई नरमी

नई दिल्ली, यूटर्न/ 08 जुलाई । सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को नरमी आई है। कीमती धातुओं में ये गिरावट डॉलर में मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जून बैठक के मिनट्स जारी होने से पहले निवेशकों की सतर्कता से आई है। इससे सोने-चांदी की कीमतें गिरी हैं। दुनिया भर के साथ ही घरेलू बाजारों में भी कीमतें नीचे आयी हैं। आज कॉम्पेक्स पर सोना 4,100 डॉलर प्रति औंस से नीचे आया। वहीं चांदी भी 60 डॉलर प्रति औंस के स्तर तक खिसकी। घरेलू मार्केट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी फिसला है। एमसीएक्स पर सोने के वायदा भाव 1,44,950 रुपये, जबकि चांदी के भाव 2,29,300 रुपये के करीब रहे। आज सोने के वायदा भाव की शुरुआत में भी कमी आई। एमसीएक्स पर सोने का बेंचमार्क अगस्त अनुबंध 192 रुपये की गिरावट के साथ ही 1,45,200 रुपये के भाव पर खुला जबकि इसका पिछला बंद भाव 1,45,392 रुपये था। सोने के वायदा भाव इस साल 1,80,779 रुपये के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचे थे।

ई-20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित : पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, यूटर्न/ 08 जुलाई । ई20 पेट्रोल को लेकर भ्रामक सूचनाओं के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है और इस पर कोई वैज्ञानिक शोध किए गए हैं, जिसका विदेशों में भी वर्षों से सफलतापूर्वक उपयोग हो रहा है। केंद्र सरकार ने ई20 पेट्रोल के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही भ्रामक सूचनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सरकार ने उन दावों को महज अफवाह बताया, जिनमें पानी की बबादी, इंजन खराब होने या बीमा समाप्त होने की बात कही जा रही थी। इथेनॉल उत्पादन में पानी की बबादी के दावे को गलत बताते हुए मंत्रालय ने कहा कि एक लीटर इथेनॉल बनाने में केवल 3 से 5 लीटर पानी लगता है, और नई फैक्ट्रियां इसे रीसायकल भी करती हैं। इथेनॉल मुख्य रूप से देश की जरूरत से बचे अतिरिक्त चावल और अब 40 प्रतिशत से अधिक मक्के से बनता है, जिसकी खेती में कम पानी लगता है। इंजन खराब होने के डर पर, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के टेस्ट का हवाला दिया गया, जिसमें कारों को 40,000 किलोमीटर और बाइकों को 20,000 किलोमीटर चलाकर देखा गया। परीक्षणों में पाया गया कि गाड़ी के चलने या माइलेज पर कोई खास नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इथेनॉल की बेहतर गुणवत्ता के कारण इंजन बेहतर काम करता है।

आरबीआई का बड़ा कदम

ग्राहकों को जबरन वित्तीय उत्पाद बेचने पर लगेगी रोक

1 जनवरी 2027 से लागू होंगे नए नियम; बैंक ग्राहकों को लोन के साथ बीमा खरीदने के लिए नहीं कर पाएंगे मजबूर

» मुंबई, यूटर्न/ 08 जुलाई ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्राहकों को गलत तरीके से बीमा, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय उत्पाद बेचने पर रोक लगाने के लिए कड़े नए नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे और ग्राहकों को जबरन बिक्री से बचाने तथा उनके हितों की रक्षा करने पर केंद्रित हैं। अब बैंक और वित्तीय संस्थान बिना ग्राहक की स्पष्ट सहमति के कोई भी उत्पाद नहीं बेच पाएंगे, और लोन के साथ बीमा खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। नए नियमों के तहत, बैंकों और एनबीएफएस को ग्राहक की स्पष्ट लिखित या डिजिटल सहमति के बिना कोई भी वित्तीय उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं होगी। यदि एक ही फॉर्म में कई उत्पाद शामिल हैं, तो प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग से सहमति लेनी होगी ताकि ग्राहक अपनी आवश्यकतानुसार चुनाव



कर सके। साथ ही, ग्राहक को लोन या अन्य बैंकिंग सेवाओं के बदले किसी खास बीमा या निवेश योजना को खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। ग्राहकों के पास अपनी पसंद की किसी भी कंपनी का वित्तीय उत्पाद चुनने की स्वतंत्रता होगी। आरबीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि बैंक ग्राहक की उम्र, आय, वित्तीय स्थिति, निवेश का फोकस और जोखिम उठाने की क्षमता को समझने के बाद ही कोई उत्पाद सुझाए। केवल कमीशन कमाने के लिए ग्राहक की जरूरत के विपरीत उत्पाद बेचना गलत माना जाएगा। ऑनलाइन बिक्री के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं, जिसमें वेबसाइटों या मोबाइल ऐप पर पहले से टिक किए गए ऑप्शन, बार-बार आने वाले पॉप-अप या ग्राहक पर जल्द फैसला लेने का दबाव बनाने वाले डिजाइन पर प्रतिबंध रहेगा। ग्राहक आसानी से किसी भी ऑफर को अस्वीकार कर सकेंगे।

महाराष्ट्र में पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया होगी हाईटेक, मुंबई में शुरू होगी वर्चुअल ऑटोप्सी सुविधा: सीएम फडणवीस

» मुंबई, यूटर्न/ 08 जुलाई ।

महाराष्ट्र सरकार राज्य में पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि मुंबई में 'नॉन-इनवेसिव पोस्ट-मॉर्टम' (वर्चुअल ऑटोप्सी) तकनीक जैसी हाई-टेक सुविधाएं शुरू की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने यह पक्का करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट समय पर मिलें। इससे पिछले दो-तीन सालों में पेंडिंग रिपोर्ट की संख्या को काफी कम करने में सफलता मिली है। यह मुद्दा सदस्य चित्रा वाघ ने उठाया था और सतेज पाटिल, अंबादास दानवे, प्रज्ञा सातव और नीलम गोहें जैसे सदस्यों ने इस पर और सवाल पूछे। सीएम फडणवीस ने नॉन-इनवेसिव तकनीक के फायदों के बारे में बताते हुए कहा कि इससे शरीर को बिना चीर-फाड़ किए उसकी जांच की जा सकती है। इस तरीके से समय की बचत होती है, कम लोगों की जरूरत पड़ती है, मानवीय गलतियाँ कम होती हैं और शरीर में होने वाले बहुत छोटे बदलावों का भी सटीक पता चल जाता है।

मुंबई के जेजे और केईएम अस्पतालों में जरूरी मशीनों के लिए टेंडर और खरीद की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभी महाराष्ट्र में 533 पोस्टमॉर्टम सेंटर काम कर रहे हैं और इस साल मई तक वहां 10,905 ऑटोप्सी की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने इन सेंटरों पर काम के भारी बोझ को देखते हुए स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए एक तय समय-सीमा में समीक्षा करने का वादा किया।

फडणवीस ने बताया कि पहले पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने में छह महीने से लेकर एक साल तक का समय लग जाता था। लेकिन, पिछले दो-तीन सालों में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में कामकाज की गति



बढ़ाकर पेंडिंग रिपोर्ट की संख्या को लगभग 3,00,000 से घटाकर 75,000 कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले तीन-चार महीनों में इस पेंडिंग काम को सामान्य स्तर पर लाना है। इसके लिए मेडिको-लीगल मामलों और सुरक्षित रखे गए विसरा (अंगों) से जुड़े मामलों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। जहां कुछ ग्रामीण सेंटरों में शव कम आते हैं, वहीं दुर्घटना-प्रवण इलाकों में सेंटरों पर बहुत ज्यादा दबाव होता है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जहां जरूरत है, वहां कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध है और सभी सेंटरों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक ऑडिट किया जाएगा। फडणवीस ने प्राइवेटों को लेकर भी कड़ी चेतावनी दी और कहा कि पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता बनाए रखना कानूनी रूप से जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि पुलिस को आधिकारिक रिपोर्ट सौंपने से पहले कोई भी जानकारी लीक करना गैर-कानूनी है और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने नवी मुंबई एयरपोर्ट के जरिए दवाओं के आयात को मंजूरी दी

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 08 जुलाई

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महाराष्ट्र में हाल ही में शुरू हुए नवी मुंबई एयरपोर्ट के जरिए दवाओं के आयात की मंजूरी दे दी है। इससे दवा की खेप के लिए तय एंटी पॉइंट्स की संख्या में इजाफा हुआ है। यह जानकारी आधिकारिक बयान में बुधवार को दी गई। ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 43ए में संशोधन करके नवी मुंबई को उन एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है जहां से दवाएं आयात की जा सकती हैं। यह कदम दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यह नोटिफिकेशन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों के तहत ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से सुझाव के बाद



जारी किया गया है।

बयान में कहा गया, 'इस संशोधन से फार्मास्युटिकल कंसाइनमेंट की आवाजाही आसान होने, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने और भारत में दवाओं के आयात के लिए एक नया विकल्प मिलने से आयातकों को ज्यादा सुविधा मिलने की उम्मीद है।' मंत्रालय ने कहा कि यह पहल नियामक ढांचे को मजबूत करने,

व्यापार को आसान बनाने और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के साथ-साथ आयात की गई दवाओं पर प्रभावी रेगुलेटरी निगरानी सुनिश्चित करने की सरकार की लगातार कोशिशों के अनुरूप है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जून में ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव दिया था ताकि जांच, टेस्ट या

एनालिसिस के लिए दवाओं के आयात की मंजूरी लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके, जिसे आमतौर पर 'फॉर्म 11' के जरिए किया जाता है।

यह संशोधन एनालिटिकल और नॉन-क्लिनिकल टेस्टिंग के मकसद से कम मात्रा में सभी दवाओं के आयात के लिए एक स्वीकृति-आधारित सिस्टम शुरू करता है।

बयान में कहा गया है कि इस संशोधन से टेस्टिंग या आरएंडडी के मकसद से कम मात्रा में दवाओं के आयात के लिए लाइसेंसिंग की जरूरतें खत्म हो जाएंगी, जिससे आवेदकों पर नियमों का पालन करने का बोझ काफी कम होने की उम्मीद है।

इस कदम से फार्मास्युटिकल सेक्टर में कारोबार में आसानी को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही रिसर्च और इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्टार्ट-अप और इंडस्ट्रीज तेजी से टेस्टिंग या एनालिसिस शुरू कर पाएंगी।



भारत के व्यापार और निवेश लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में आईसीएआई निभा सकता है अहम भूमिका: गोयल

नई दिल्ली, यूटर्न/ 08 जुलाई । केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के नेतृत्व के साथ बैठक के बाद कहा कि संस्थान के साथ मजबूत सहयोग भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देने और वैश्विक व्यापार में देश की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बैठक में सरकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पेशे के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई, ताकि व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और मजबूत किया जा सके। पीयूष गोयल ने कहा कि बैठक में इस बात पर भी विचार-विमर्श हुआ कि बदलते वैश्विक आर्थिक माहौल में व्यवसायों को नए अवसरों का लाभ उठाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका कैसे और अधिक प्रभावी बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के बदलते परिदृश्य के अनुरूप कारोबारों को खुद को ढालने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

जूता शोरूम की छत पर आग, 11 गाड़ियों ने डेढ़ घंटे में पाया काबू

» गाजियाबाद, यूटर्न/ 08 जुलाई

घंटाघर स्थित जवाहर गेट से सटे विंग्स शूज शोरूम की चौथी मंजिल पर मंगलवार दोपहर जनरेटर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दमकल टीम को पड़ोसी भवनों की छतों की दीवार तोड़कर मौके तक पहुंचना पड़ा। 11 दमकल गाड़ियों की मदद से करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे आग लगने की सूचना मिली। नगर कोतवाली से तुरंत दमकल टीम रवाना की गई। आग चौथे फ्लोर पर लगी थी और देखते ही देखते नीचे गोदाम तक पहुंच गई। धुएँ का गुबार देखकर आसपास के दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। सभी अपनी दुकानों को लेकर चिंतित हो उठे।

आग की विकरालता को देखते हुए सभी फायर स्टेशनों से कुल 11 गाड़ियाँ मौके पर बुलाई गईं। भवन की छत तक पहुंचने में दिक्कत आने पर



आसपास के भवनों की छतों तक हौजलाइन फैलाकर छत की दीवारें तोड़ी गईं। भवन के अंदर तेज ताप और धुआँ होने के कारण फायर कर्मियों ने बीएसेट पहनकर अंदर प्रवेश कर आग बुझाने का काम शुरू किया।

अधिकारियों ने बताया कि समय रहते आग पर काबू पाने से आसपास स्थित अन्य दुकानों और शोरूम को सुरक्षित बचा लिया गया।

मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।

हत्या और सदिग्ध मौत के मामलों में अब फॉरेंसिक विशेषज्ञ की निगरानी में होगा पोस्टमार्टम

» गाजियाबाद, यूटर्न/ 08 जुलाई

हत्या, सदिग्ध मौत और अन्य गंभीर मामलों की जांच को अधिक पारदर्शी व वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब ऐसे मामलों में पोस्टमार्टम फॉरेंसिक विशेषज्ञों की निगरानी व भागीदारी में कराया जाएगा।

शासन का मानना है कि इससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही आपराधिक मामलों की विवेचना व अभियोजन को मजबूत आधार मिलेगा। इसके अलावा सामान्य चिकित्सकों को ओपीडी में मरीजों के उपचार के लिए अधिक समय मिल सकेगा, क्योंकि अब तक रोजाना एक चिकित्सक की पोस्टमार्टम ड्यूटी लगाई जाती थी।

प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के महानिदेशक की ओर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जहां फॉरेंसिक विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए गठित मेडिकल बोर्ड का अनिवार्य सदस्य बनाया जाएगा। साथ ही पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के



दिशा-निर्देशों, निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरी की जाएगी। जिले में गंभीर मामलों में जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से मेडिकल बोर्ड गठित किया जाता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसे बोर्ड में फॉरेंसिक विशेषज्ञ की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सचिन चंद्र वैश्य ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन के लिए जिले में संबंधित अधिकारियों व चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से पोस्टमार्टम प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष, वैज्ञानिक और न्यायिक आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। इससे मृत्यु के कारणों का सटीक निर्धारण करने में सहायता मिलेगी। अदालतों में प्रस्तुत होने वाले साक्ष्यों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

ईडी ने अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के पूर्व सीएफओ को गिरफ्तार किया

» गुरुग्राम, यूटर्न/ 08 जुलाई

ईडी ने मेसर्स अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स अपोलो इंटरनेशनल लिमिटेड) के पूर्व सीएफओ राकेश गुप्ता को मंगलवार को गिरफ्तार किया है। ईडी ने ये गिरफ्तारी इंदरजीत सिंह और अन्य के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में की है। ईडी की ओर से कहा गया कि यह गिरफ्तारी गुरुग्राम स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा जारी चार समनों का अनुपालन न करने और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किए जाने के बाद की गई।



गिरफ्तारी के बाद आरोपी को गुरुग्राम विशेष पीएमएलए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वहां से आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर लेकर ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इंदरजीत सिंह और उसके सहयोगियों के

पुलिस ने कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' की सलाह दी, कल की बारिश में लगा था लंबा जाम

» गुरुग्राम, यूटर्न/ 08 जुलाई

एनसीआर में पहली जोरदार मानसूनी बारिश ने तमाम सरकारी व्यवस्थाओं को नाकाफी साबित करते हुए आगामी व्यवस्थाओं पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी क्रम में गुरुग्राम पुलिस ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' की सलाह दी गई है।

ट्वीट के मुताबिक गुरुग्राम में हो रही और आगे होने वाली भारी बारिश को देखते हुए, शहर की मुख्य सड़कों और चौराहों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की पूरी संभावना है। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, ट्रैफिक का अनावश्यक दबाव कम करने और सड़क प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की मदद करने के लिए, गुरुग्राम पुलिस यह सावधानी वाली सलाह जारी कर रही है। कल बारिश के बाद साइबर सिटी में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई।



पुलिस अधिकारियों के बारिश के दौरान जाम न लगने देने के दावे एक ही बारिश ने खोखले साबित कर दिए। मंगलवार को बारिश के बाद दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) पर नरसिंहपुर के पास दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाली लेन पर सड़क धंस गई। इस कारण एनएच-48 की दो लेन को बंद करना पड़ा।

इसके बाद हाईवे पर 12 किलोमीटर से लंबा जाम लग गया और पुलिस को रूट डायवर्ट करना पड़ा। दिल्ली-जयपुर हाईवे

(एनएच-48) पर लगे जाम का असर शहर के शंकर चौक, इफको चौक, सिग्नेचर टावर चौक, राजीव चौक व हीरो होंडा चौक पर भी दिखाई दिया। एनएच-48 पर दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाली लेन पर जाम लगा होने के कारण इन सभी चौक से वाहन हाईवे पर नहीं चढ़ पा रहे थे।

इस कारण सभी चौक पर वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। वाहनों को निकालने में यातायात पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत

करनी पड़ रही थी लेकिन वाहनों के चलने की जगह नहीं होने के कारण चौक पर जमा लगा गया था।

दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) पर सड़क धंसने के बाद लगे जाम के कारण यातायात पुलिस को रूट डायवर्ट करना पड़ा। जयपुर की ओर जाने वाले वाहनों को राजीव चौक से वाहनों को गुरुग्राम-सोहना रोड से हीरो होंडा निकाला गया। वहीं, खेड़कीदौला की ओर जाने वाले वाहन चालकों को पुलिसकर्मियों द्वारा एसपीआर रोड का प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा था। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस से संपर्क करके वाहनों को दिल्ली-जयपुर हाईवे की बजाय द्वारका एक्सप्रेसवे प्रयोग करने के लिए कहा गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने शिवमूर्ति चौक के पास से द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया, ताकि दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) पर वाहनों के दबाव को कम किया जा सके।

राजपार्क में पुरानी रंजीश का खूनी अंत शोक में था परिवार, तभी अचानक आए 10 हमलावर और चाकू से किए ताबड़तोड़ वार

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 08 जुलाई

राजपार्क इलाके में सोमवार की रात पुरानी रंजीश में हमलावरों ने दो भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। इसमें 45 साल के महेश की मौत हो गई, वहीं उनके चचेरे भाई मुकेश (35) घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत चार को पकड़ा है। पहचान प्रिंस उर्फ अरुण, राहुल और भरत के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपी के परिवार के हवलदार प्रदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, जिसपर पीड़ित परिवार ने मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक महेश परिवार के साथ क्यू ब्लाक मंगोलपुरी में रहते थे। परिवार में पत्नी संगीता और दो बेटे हैं।

पड़ोस में रहने वाले दोनों परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी चल रही है, जिसकी वजह से चाकू से हमला किया गया। पिछले एक साल के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से दो-दो मामले पहले ही दर्ज किए जा चुके थे। मुकेश ने बताया कि दो जुलाई को उनके ताऊ का निधन हो गया था।

परिवार वाले वहीं बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी 10 की संख्या में हमलावर आए। उन लोगों ने उसपर चाकू से हमला कर दिया। बचाव करने पर चाकू उसके जांघ में लगा। उसके भाई महेश बचाव के लिए आए तो चाकू उनके पीठ पर मार दिया।

घायल मुकेश ने बताया कि आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार वाले उनके परिवार को घर बेचकर यहाँ से भगाना चाहते हैं। आरोपी परिवार उनके घर को



- दोनों पड़ोसियों में थी दुश्मनी
- पीड़ित परिवार में हुई थी मौत
- वहीं बैठकर बातचीत कर रहे थे सभी
- तभी 10 की संख्या में आए हमलावर

खरीदकर अपने घर के साथ मिलाकर उसे बड़ा करना चाहते हैं। एक साल पहले आरोपियों ने उनकी बहन को चाकू मारा था। उसके एक माह बाद आरोपियों ने उनके भाई नरेश पर चाकू से हमला किया था। अब उन लोगों ने उनके एक भाई की हत्या कर दी और उसपर जानलेवा हमला किया है।

पहले के मामलों में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। पीड़ित परिवार की ओर से सिपाही प्रदीप पर लगाए आरोपों की जांच की जा रही है। प्रदीप की इस मामले में सलिपता आने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विक्रम सिंह, पुलिस उपायुक्त बाहरी जिला, दिल्ली

संक्षिप्त खबरें

तेज रफ्तार कैंटर, ऑटो के बीच टक्कर लगने से युवती का हाथ कटा

लोनी, यूटर्न/ 08 जुलाई। बंधला चिरौड़ी मार्ग निठोरा गेट के सामने मंगलवार सुबह तेज रफ्तार कैंटर से ऑटो की टक्कर हो गई। घटना में ऑटो में सवार युवती का हाथ कटकर नीचे गिर गया। जबकि अन्य सवारियों को मामूली चोट आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है।

सिरौली गांव निवासी राहुल ने बताया कि उनकी बहन काजल गाजियाबाद में ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख रही है। मंगलवार सुबह करीब नौ बजे बहन घर से गाजियाबाद घंटाघर के लिए निकली थी। करीब साढ़े नौ बजे जब ऑटो बंधला चिरौड़ी स्थित निठोरा गेट के सामने पहुंचा तो सामने चल रहे वाहन को ओवरटेक करते समय ऑटो सामने से आ रहे कैंटर से टकरा गया। टक्कर लगने के बाद ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया और बहन का सीधा हाथ कट कर रोड पर गिर गया। हादसे के बाद ऑटो व कैंटर चालक मौके से भाग गए। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने काजल को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया और वहां से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पीड़िता का गंभीर हालत में निजी अस्पताल में उपचार जारी है। कैंटर व ऑटो को कब्जे में लेकर चालकों की तलाश की जा रही है।

नहाती महिला का वीडियो बनाने का आरोप, विरोध पर मारपीट

गाजियाबाद, यूटर्न/ 08 जुलाई। मसूरी थाना क्षेत्र के एक गांव में नहा रही महिला का चुपके से अश्लील वीडियो बनाने और विरोध करने पर मारपीट व धमकी का मामला सामने आया है। पीड़िता के पति ने पुलिस को शिकायत में बताया कि सोमवार शाम करीब चार बजे उनकी पत्नी घर में नहा रही थी। इसी दौरान गांव के ही एक युवक ने घर की छत पर चढ़कर मोबाइल से महिला का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।

विरोध करने पर आरोपी भड़क गया। आरोप है कि वह घर में घुसकर गाली-गलौज करने लगा। पीड़ित परिवार के साथ बदसलूकी की, धक्का-मुक्की की और पति के कपड़े तक फाड़ दिए। आरोपी ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।

एसपी अजय कुमार ने बताया कि अभी मामले की लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

‘इंस्टाग्राम और डेटिंग ऐप्स से नहीं मिलेगी मंजिल कंगना रनौत का युवाओं के नाम संदेश



मशहूर अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने मॉडर्न डेटिंग पर अपनी राय साझा की है। बुधवार को कंगना ने इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन पर एक लंबा नोट साझा किया, जिसमें उन्होंने युवाओं को सलाह दी। उन्होंने लिखा, 'व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, डेटिंग ऐप्स, बेंचिंग, घोस्टिंग, डबल/ट्रिपल डिजिट बाँडी काउंट्स, क्रम्बिंग, सीइंग, टेस्टिंग, फिल्टर्स, स्टोरीज, ड्रम्स, क्लब्स और बहुत कुछ हैं, लेकिन फिर भी यह काफी नहीं है। किसी लक्ष्य या उद्देश्य के बिना पैशन कई तरह की बेतरतीब और सेल्फ-डिस्ट्रिक्टिव एक्सप्रेशन का रूप ले सकता है। इसलिए जुनून होना जरूरी है, लेकिन वह आपके करियर या किसी हुनर के प्रति होना चाहिए। मैं युवाओं से कहना चाहती हूँ कि अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगाएं।' उन्होंने लिखा, 'खुले दिमाग से सोचें, लेकिन जीवन को रूढ़िवादी (कंजरवेटिव) तरीके से जिएं। इससे आप बोरियत, नकारात्मकता, अवसाद और ऐसी कई दूसरी परेशानियों से बच सकते हैं।'

आधुनिक डेटिंग का असर समाज में विवाह संबंधों की प्रकृति पर

भी पड़ा है, जिससे वैवाहिक मामलों से जुड़े अपराधों में वृद्धि देखी जा रही है।

इससे पहले कंगना ने स्ट्रीमिंग रियलिटी शो 'लॉकअप' के नए सीजन में जेलर की भूमिका निभा रहे फराह खान और रितेश देशमुख के साथ हिस्सा लिया था।

फराह और रितेश के प्रदर्शन की सराहना करते हुए अभिनेत्री ने कहा कि दोनों ने प्रतियोगियों के साथ व्यवहार करते समय पूरी निष्पक्षता दिखाई है। साथ ही, जब टास्क की बात आती है तो वे किसी भी तरह का समझौता नहीं करते। शो के पहले सीजन की होस्ट रह चुकी कंगना ने कहा, 'फराह और रितेश ने 'लॉकअप' को वही मजबूत नेतृत्व दिया है, जिसकी इसे जरूरत थी।

वे निष्पक्ष, निडर और प्रतियोगियों को जिम्मेदारी का एहसास कराने के मामले में बिल्कुल समझौता न करने वाले रहे हैं। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर मंडी सीट से जीता था।



अभिनेत्री आकांक्षा चमोला दोबारा नहीं करेंगी शादी, अकेली गुजारेगी जिंदगी

अभिनेता गौरव खन्ना से तलाक और खुद के बायसेक्शुअल होने की चर्चाओं के बाद अभिनेत्री आकांक्षा चमोला ने कहा है कि वह दोबारा शादी नहीं करेंगी। फराह खान और रितेश देशमुख के होस्ट किए जाने वाले नेटफ्लिक्स शो 'लॉकअप: सच या सजा' के हालिया एपिसोड में आकांक्षा अपनी करीबी दोस्त पामेला सेरेना के साथ जेल में दिल की बातें करती नजर आईं। आकांक्षा ने पामेला से कहा कि जब उनकी शादी गौरव खन्ना से हुई थी, तब उनकी उम्र 24 साल थी। इस पर पामेला ने कहा कि वह अभी भी युवा हैं और उन्हें आगे चलकर कोई अच्छा जीवनसाथी मिल सकता है। आकांक्षा ने जवाब दिया, 'नहीं, मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती। मेरा मन अब शादी से भर गया है। लेकिन जिंदगी में पहली बार मैं अकेले रहूंगी। न मैं अपने माता-पिता के घर रहूंगी और न ही पति के घर। मेरा अपना घर होगा और मैं आगे की जिंदगी अकेले ही बिताऊंगी।' फिलहाल शो में आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, सुनीता आहूजा, राम कपूर, श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, सूपी मोतीवाला, धीरज धूपर, माधुरी जैन ग्रोवर, रियाज अली और वरुण यादव उर्फ 'लैला' जैसे कई लोकप्रिय चेहरे नजर आ रहे हैं। 'लॉकअप' का पहला सीजन साल 2022 में आया था, जिसे कंगना रनौत ने होस्ट किया था।

मनीष पॉल की मां का 77 वर्ष की उम्र में निधन, अभिनेता की टीम ने साझा किया भावुक संदेश



अभिनेता, टीवी होस्ट और एंकर मनीष पॉल की मां का बुधवार को दिल्ली में 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एक्टर की टीम ने उनके निधन की खबर दी। उन्होंने बताया, 'बड़े दुख के साथ हमें यह बताना पड़ रहा है कि आज दिल्ली में एक्टर मनीष पॉल की मां का निधन हो गया। उनकी उम्र 77 वर्ष थी। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।' बता दें कि मनीष पॉल का पारिवारिक जीवन काफी निजी रहा है और उन्होंने इसके बारे में पब्लिक में ज्यादा कुछ नहीं बताया है। उनकी शादी बचपन की दोस्त और लंबे समय की पार्टनर संयुक्ता पॉल से हुई है। उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा - सायशा और एक बेटा - युवान। अपने बिजी करियर के बावजूद, वह परिवार को लाइमलाइट से दूर रखते हैं और साथ रहने को अहमियत देते हैं। इससे पहले मनीष पॉल ने अपनी फिल्म के सेट से कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें शेयर की थीं, जिनमें वह विक्रम फडनीस और एक्ट्रेस सैयामी खेर के साथ नजर आ रहे थे। इस फिल्म में ताहिर राज भसीन भी हैं। उन्होंने लिखा, 'मैं विक्रम फडनीस को एक दशक से ज्यादा समय से जानता हूँ। हमारी बहुत सारी मजेदार बातें होती थीं, जब तक कि उन्होंने मुझे यह रोल नहीं दिया। सेट पर वह बिल्कुल अलग इंसान होते हैं। पूरे भरोसे, जज्बात, समझदारी और एक प्रोफेशनल डायरेक्टर की सोच के साथ। आप पर बहुत गर्व है, विक्रम और इस रोल और इस फिल्म के लिए आपका शुक्रिया। सेट पर बिताया हर पल बहुत पसंद आया। दर्शकों को आपका बनाया जादू देखने का बेसब्री से इंतजार है।'

सैमसन इन कारणों से टीम इंडिया से बाहर हुए

» मुंबई, यूटर्न/ 08 जुलाई ।

भारतीय क्रिकेट में कुछ ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका करियर संजू सैमसन जितना उतार-चढ़ाव भरा रहा हो। हाल ही में संपन्न हुए टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम को जीत दिलाने वाले सैमसन को अब टीम में अपनी जगह बनाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आगामी जिम्बाब्वे दौरे के लिए भी उन्हें टी20 टीम में जगह नहीं मिली है। जिससे प्रशंसक हैरान हैं। इससे ये सवाल उठने लाजिमी है कि ऐसा क्या हुआ कि विश्व कप हीरो अचानक ही चयनकर्ताओं की प्राथमिकता सूची से बाहर हो गया है।

तीन महीने पहले ही विश्व कप में अपनी निडर और मैच विजेता पारियों से टीम को मजबूत करने वाले सैमसन का बल्ला उसके बाद से खामोश है। आयरलैंड दौरे पर भी वह रन बनाने में सफल रहे। अच्छी शुरुआत को वे बड़ी पारी में नहीं बदल पाए और स्ट्राइक रोटेट करने में भी संघर्ष करते दिखे। इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर पहले टी20 में भी उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दूसरे मैच में युवा वैभव सूर्यवंशी के लिए प्लेइंग-11 से बाहर बैठना पड़ा। किसी भी खिलाड़ी के लिए बेंच पर बैठना मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, और अब जिम्बाब्वे सीरीज से पूरी तरह बाहर होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि



चयनकर्ताओं की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। सैमसन के करियर पर मंडराते इस संकेत के पीछे तीन प्रमुख कारण दिखाई देते हैं। पहला, उनका फॉर्म। विश्व कप की शानदार लय को वे बरकरार नहीं रख पाए। आयरलैंड और इंग्लैंड में छोटी पारियां उनके खिलाफ गईं, जो टी20 क्रिकेट में चयन पर सीधा असर डालती हैं। दूसरा, टीम इंडिया में विकेटकीपर-बल्लेबाज की जगह के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा। भारतीय टीम में प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों की लंबी कतार है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन से शीर्ष क्रम में कई विकल्प पेश कर रहे हैं।

फ्रांस के साथ क्वार्टर-फाइनल मुकाबले से पहले अबूखलाल बोले, 'मोरक्को को मिलकर डिफेंस करना होगा'

» रबात, यूटर्न/ 08 जुलाई ।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच से पहले मोरक्को के पूर्व विंगर जकारिया अबूखलाल ने 'एटलस लायंस' को चेताया है। अबूखलाल का मानना है कि मोरक्को की टीम 10 जुलाई को फ्रांस के खिलाफ सिर्फ डिफेंस पर निर्भर नहीं रह सकती। जब शुक्रवार को दोनों टीमों वर्ल्ड कप में अपनी पुरानी प्रतिद्वंद्विता को फिर से शुरू करेंगी, तो उन्हें बॉल अपने पास रखते हुए हिम्मत दिखानी होगी।

पिछली बार कतर में 2022 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया था। अबूखलाल उस सेमीफाइनल में दूसरे हाफ में सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर उतरे थे, उन्होंने कहा कि फ्रांस दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है क्योंकि वे छोटी-छोटी गलतियों का भी फायदा उठाने में माहिर हैं। अबूखलाल ने फीफा से कहा, 'मुझे वह तीव्रता और यह एहसास याद है कि हम गेम में बने हुए थे। भले ही हम पीछे थे, लेकिन विश्वास बनाए रखे हुए थे और कोशिश करते रहे। फ्रांस का सामना करना मुश्किल था क्योंकि वे हर छोटी गलती की सजा देते थे। उनके पास रफ्तार, अनुभव और ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक पल में मैच का नतीजा बदल सकते हैं। कभी-कभी आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन एक ट्रांजिशन सब कुछ बदल सकता है।'

टोरिनो के विंगर का मानना है कि मोरक्को



के लिए चुनौती सिर्फ फ्रांस के स्टार किलियन एम्बापे को रोकना नहीं है, क्योंकि 'लेस ब्लूज' (फ्रांस की टीम) के पास पूरे मैदान पर मैच जिताने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं।

अबूखलाल ने कहा, 'बेशक, एम्बापे दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं, इसलिए आपको उनसे सावधान रहना होगा, लेकिन फ्रांस का मतलब सिर्फ एम्बापे नहीं है। उनके पास हर जगह बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मोरक्को को मिलकर डिफेंस करना होगा, एकजुट रहना होगा और ट्रांजिशन के दौरान फ्रांस को ज्यादा जगह नहीं देनी होगी, लेकिन उन्हें बॉल के साथ हिम्मत भी दिखानी होगी। फ्रांस के खिलाफ आप सिर्फ डिफेंस करके नहीं टिक सकते। आपको ऐसे पलों की जरूरत होती है जब आप उन्हें भी डिफेंस करने पर

मजबूर करें।'

हालांकि अबूखलाल को मोरक्को की 2026 वर्ल्ड कप टीम के लिए नहीं चुना गया था, लेकिन वे टीम की प्रगति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और मानते हैं कि कतर में शानदार प्रदर्शन के बाद से मौजूदा टीम काफी परिपक्व हो गई है। उन्होंने कहा, 'परिपक्वता। वे शांत, आत्मविश्वासी और एकजुट दिखते हैं। उन्हें इस स्टेज पर पहुंचकर कोई हैरानी नहीं होती। वे अपनी ताकत के हिसाब से खेलना चाहते हैं, चाहे सामने कोई भी टीम हो।' फ्रांस की काबिलियत को स्वीकार करने के बावजूद अबूखलाल का मानना है कि वर्ल्ड कप में एक और शानदार प्रदर्शन से फुटबॉल की दिग्गज टीमों के बीच मोरक्को की जगह सुनिश्चित हो जाएगी।

संक्षिप्त खबरें

ईरान ने कुवैत एवं
बहरीन में अमेरिकी
ठिकानों पर किये हमले

तेहरान, यूटर्न/ 08 जुलाई । ईरान ने बुधवार को कहा कि उस पर अमेरिकी हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने मंगलवार रात कहा था कि अमेरिका ने 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य में तीन वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में' ईरान के खिलाफ सिलसिलेवार हमले शुरू किये हैं। सेंटकॉम ने बाद में बुधवार को कहा कि उसने अपना अभियान पूरा कर लिया है, जिसमें वायु रक्षा प्रणाली, जहाज-रोधी मिसाइल प्रणाली और छोटी नावों सहित 80 से अधिक ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। फार्स समाचार एजेंसी ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के एक बयान के हवाले से कहा, 'इस आक्रामकता की शुरूआत में आईआरजीसी की नौसेना और वायुसेना ने एक संयुक्त अभियान चलाया और ड्रोन व मिसाइलों का उपयोग करके बहरीन में सलमान बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के साथ-साथ कुवैत में अली अल सलेम हवाई ठिकाने पर हमला किया।

लॉरेंस और गोल्डी बराइ
नेटवर्क पर कसा वैश्विक
शिकंजा, 24 घरे गए

वॉशिंगटन, यूटर्न/ 08 जुलाई । अमेरिका, कनाडा और यूरोप की सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त अभियान 'ऑपरेशन हार्ड बॉल' के तहत संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराइ से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया है। इस बहुराष्ट्रीय अभियान में कुल 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 37 लोगों के खिलाफ तीन अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में 13 अमेरिका, तीन कनाडा और एक स्पेन से पकड़ा गया है, जबकि सात आरोपी पहले से ही हिरासत में थे। जांच एजेंसियां भारत, अमेरिका और यूरोप में छिपे 10 अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। अभियान का उद्देश्य हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली और सीमा पार संगठित अपराध से जुड़े नेटवर्क को ध्वस्त करना बताया गया है। कार्रवाई के दौरान करीब एक मीट्रिक टन कोकीन, एक किलोग्राम हेरोइन, 40 हजार अमेरिकी डॉलर नकद और एक दर्जन अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए।

इंडोनेशियाई राष्ट्रपति बोले- मैं भारत की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता, पर ?

» जकार्ता, यूटर्न/ 08 जुलाई ।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनके और भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त की है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नई गर्मजोशी आई है। जकार्ता में आयोजित एक कार्यक्रम में, राष्ट्रपति सुबियांतो ने प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में कहा कि वह भारत की राजनीति में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन वह नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने अपने करीबी सहयोगियों और सहकर्मियों को भी इस बात का गवाह बताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने मंच के सामने उपस्थित होकर हाथ



जोड़कर इस अभिवादन का जवाब दिया।

इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने अपने देशवासियों से भारत के अनुभवों से सीखने का आ'न किया, क्योंकि उनके अनुसार भारत ने इंडोनेशिया की सभ्यता और संस्कृति को काफी

प्रभावित किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी भाषा का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा संस्कृत से आया है और उनके कई नाम भी संस्कृत मूल के हैं, जो दोनों देशों के बीच एक विशेष निकटता का संकेत देता है। उन्होंने 2025 में भारत के

गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने को अपने लिए सम्मान की बात बताया, यह पदभार संभालने के केवल तीन महीने बाद की बात थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की भारतीय डीएनए संबंधी टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि आपके इस बयान ने भारतवासियों का दिल छू लिया है। यह डीएनए आपसी विश्वास, साझा विरासत और साझा स्मृतियों से बना है। प्रधानमंत्री मोदी की यह तीन देशों की यात्रा का पहला पड़ाव है, जिसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर के साथ हुई, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल के मामले में भारत को एक बड़ी डील भी मिली है, जो

रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

डीएनए में भी भारतीय अंश राष्ट्रपति सुबियांतो ने अपने संबोधन में एक दिलचस्प दावा भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके भीतर भारतीय डीएनए है। उन्होंने बताया कि अपनी भारत यात्रा से ठीक पहले उन्होंने जीनोम अनुक्रमण परीक्षण कराया था, जिसमें भारतीय डीएनए के अंश पाए गए। हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि शायद यही कारण है कि उन्हें भारतीय संगीत सुनते ही उनके पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा कि उनके मंत्री और जनरल भी नाचने-गाने के शौकीन हैं और शायद उनमें से ज्यादातर के डीएनए में भी भारतीय अंश हो।

ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा में कथित धोखाधड़ी
की जांच शुरू की, बड़ी कंपनियां भी रडार पर

□ डी 'एस्पॉसिटो का आरोप है कि विदेशी श्रम कार्यक्रमों में होने वाली धोखाधड़ी का संबंध बड़े आपराधिक नेटवर्क से भी हो सकता है।

□ श्रम विभाग के इंस्पेक्टर जनरल एंथनी डी 'एस्पॉसिटो ने कहा कि यह जांच विदेशी श्रम से जुड़े कथित धोखाधड़ी के खिलाफ इंस्पेक्टर जनरल के दफ्तर की अब तक की सबसे सख्त कार्रवाइयों में से एक होगी।

» वॉशिंगटन, यूटर्न/ 08 जुलाई ।

ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी और 'पर्म' रोजगार वीजा से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामलों की जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के श्रम विभाग के इंस्पेक्टर जनरल ने बताया कि जांचकर्ताओं ने मजदूरों की तस्करी और विदेशी कर्मचारियों से जुड़े कार्यक्रमों के गलत इस्तेमाल की आशंका में बड़े स्तर पर जांच शुरू की है और इसके तहत दर्जनों सबपोना नोटिस जारी किए जा चुके हैं। श्रम विभाग के इंस्पेक्टर जनरल एंथनी डी 'एस्पॉसिटो ने कहा कि यह जांच विदेशी श्रम से जुड़े कथित धोखाधड़ी के खिलाफ इंस्पेक्टर जनरल के दफ्तर की अब तक की सबसे सख्त कार्रवाइयों में से एक होगी। उन्होंने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा, 'इसमें कोई शक नहीं है कि यह प्रशासन विदेशी श्रम धोखाधड़ी के खिलाफ अब तक की सबसे आक्रामक



कार्रवाई करेगा। हमने पहले ही दर्जनों सबपोना जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की फ्रॉड टास्क फोर्स की मदद से हर सुराग की जांच की जाएगी। डी 'एस्पॉसिटो ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर सुराग तक पहुंचा जाए। उन्होंने बताया कि कुछ व्हिसलब्लोअर्स ने 'कॉग्निजेंट जैसी बड़ी कंपनियों' से जुड़े मामलों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जांच आगे बढ़ने पर उनकी टीम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की फ्रॉड टास्क फोर्स के साथ मिलकर काम करेगी। डी 'एस्पॉसिटो का आरोप है कि विदेशी

श्रम कार्यक्रमों में होने वाली धोखाधड़ी का संबंध बड़े आपराधिक नेटवर्क से भी हो सकता है।

उन्होंने कहा, 'यह एक और उदाहरण है कि कैसे धोखाधड़ी हिंसक अपराधों को बढ़ावा देती है। विदेशी श्रम से जुड़े कई वीजा और मानव तस्करी के मामले ड्रग कार्टेल और अंतरराष्ट्रीय गैंग से जुड़े होते हैं। यह काम सिर्फ अमेरिका को सुरक्षित बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि लोगों के लिए इसे अधिक किफायती बनाने के लिए भी जरूरी है।'

उन्होंने कहा कि कथित धोखाधड़ी सिर्फ फैक्ट्रियों जैसे क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। ये सिर्फ फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे लोग मेडिकल सुविधाओं और डॉक्टरों के क्लीनिकों में भी काम कर रहे हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यहां तक कि इससे किसी की जान भी जा सकती है।

उन्होंने बताया कि जांच में अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों में फैक्ट्रियों, बंदरगाहों, अस्पतालों और नर्सिंग सुविधाओं से जुड़े मामलों की भी जांच होगी। इंस्पेक्टर जनरल ने कहा कि यह जांच न्याय विभाग और फेडरल प्रॉसिक्यूटर के साथ मिलकर की जा रही है। जो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, उन्हें ढूंढा जाएगा, उनकी जांच होगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। डी 'एस्पॉसिटो ने यह भी कहा कि इस जांच का एक मकसद यह सुनिश्चित करना है कि रोजगार आधारित वीजा कार्यक्रमों के गलत इस्तेमाल की वजह से अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित न हों।

पाकिस्तान का बोइंग
737 कार्गो विमान
अरब सागर में लापता

इस्लामाबाद, यूटर्न/ 08 जुलाई । पाकिस्तान का एक मालवाहक विमान मंगलवार रात को रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया, जिसमें चालक दल के पांच सदस्य सवार थे। बोइंग 737-400 कार्गो विमान शांजहा से कराची जा रहा था, लेकिन उड़ान के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी आने के बाद इसका एयर ट्रेफिक कंट्रोल (एटीसी) से संपर्क टूट गया। शुरूआती आंकड़ों के मुताबिक, आशंका जताई जा रही है कि विमान कराची के दक्षिण-पश्चिम में अरब सागर में क्रैश हो गया है। इस घटना के बाद समुद्र में बड़े पैमाने पर तलाशी और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अनुसार, विमान ने पाकिस्तानी समयानुसार रात 9:18 बजे कराची की ओर उड़ान भरते समय नेविगेशन सिस्टम में खराबी की सूचना दी थी। स्थानीय एयर ट्रेफिक कंट्रोल ने तुरंत विमान को मार्गदर्शन देने की कोशिश की, लेकिन मात्र तीन मिनट बाद ही रडार सिस्टम पर विमान तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखा और संचार पूरी तरह से कट गया। अथॉरिटी के बयान के मुताबिक, संपर्क टूटते समय फ्लाइट कराची से लगभग 155 समुद्री मील (287 किलोमीटर) पश्चिम में थी।

विवाद के बाद बोले ट्रंप- मेलोनी को मैं बहुत पसंद करता हूं

» अंकारा, यूटर्न/ 08 जुलाई ।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलोनी को लेकर अपने रुख में नरमी दिखाते हुए उनकी खुलकर सराहना की है। तुर्किये की राजधानी अंकारा में राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान ट्रंप ने मेलोनी को शानदार महिला बताया और कहा कि वह उन्हें पसंद करते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दोनों नेताओं के रिश्तों में कुछ समय के लिए तनाव आ गया था। ट्रंप के अनुसार इसकी वजह ईरान से जुड़े मुद्दे पर इटली का अमेरिका का साथ नहीं देना था। उनके इस बयान को दोनों नेताओं के बीच संबंधों में



संभावित सुधार के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मेलोनी पर किसी तरह का बड़ा दबाव नहीं बनाया था, लेकिन ईरान से जुड़े मामले में इटली

के रुख से वह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने माना कि इसी कारण दोनों पक्षों के संबंध प्रभावित हुए। इसके बावजूद उन्होंने दोहराया कि मेलोनी एक मजबूत और प्रभावशाली नेता हैं। हालांकि ट्रंप ने यह

भी कहा कि उनके अनुसार उस मुद्दे पर इटली का फैसला सही नहीं था और मेलोनी से गलती हुई थी।

दोनों नेताओं के बीच विवाद उस समय बढ़ गया था, जब ट्रंप ने दावा किया था कि फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी कई बार उनके साथ तस्वीर खिंचवाने का आग्रह कर रही थीं। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया था कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियानों के दौरान इटली ने अपने हवाई अड्डों और रनवे के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका नाटो सहयोगियों की सुरक्षा पर भारी खर्च करता है, लेकिन इसके बावजूद इटली ने अपेक्षित सहयोग नहीं दिया।

बरईपुर नाबालिग बलात्कार एवं हत्या मामले का
मुख्य आरोपी भागने की कोशिश में मारा गया

कोलकाता, यूटर्न/ 08 जुलाई । पश्चिम बंगाल के बरईपुर में नाबालिग के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी प्रभास मंडल घटनास्थल से भागने की कोशिश करने के दौरान पुलिस की गोली से मारा गया। पुलिस के अनुसार, इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किये गये मंडल को जांच के लिए बुधवार देर रात करीब 12.45 बजे घटनाक्रम को समझने के लिए सूर्यपुर में घटनास्थल पर ले जाया गया था। पुलिस ने दावा किया कि इस प्रक्रिया के दौरान मंडल ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों से एक हथियार छीन लिया और भागने का प्रयास किया। अधिकारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उसने कथित तौर पर पुलिस पर गोलीबारी कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। मंडल को तुरंत बरईपुर उप-मंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी संख्या में केंद्रीय बलों को अस्पताल में तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि घटनाक्रम को दोहराना (सीन रिक्रिएशन) इसलिए जरूरी समझा गया क्योंकि आरोपी पूछताछ के दौरान कथित तौर पर गुमराह करने वाले और असंगत बयान दे रहा था और जांचकर्ताओं का सहयोग नहीं कर रहा था।